भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3331

16 मार्च, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि बीमा के लिए डाटा संग्रहण

3331. श्री असादुद्दीन औवैसी:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि क्षेत्रों में सुदूर संवेदी डाटा संग्रहण के लिए ड्रोन तैनात किए जाने हेतु डीजीसीए से सशर्त सहमति प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कदम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत त्वरित दावा के लिए बीमा यूनिट में यथार्थ फसल उत्पादन/हानि का आकलन करने में किस प्रकार सहायता मिलेगी; और

(घ) सरकार के इस कदम से किसानों को कितना लाभ मिलने की संभावना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) नामक इस योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का उपयोग परिकल्पित है। इस योजना के तहत प्रावधानों के अनुसार दावों की गणना अधिसूचित बीमा ईकाई स्तर पर अधिसूचित फसलों के लिए अपेक्षित फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) की संख्या के आधार पर संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत उपज डेटा के आधार पर की जाती है। यह एक मानविक प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है जिसके कारण कई बार किसानों के दावों में विलंब होता है। तदनुसार कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पुर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी) के माध्यम से शीघ्र उपज अनुमान और दावों का समय पर निपटान करने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकीयों का उपयोग करके ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्यक्ष उपज अनुमान के लिए प्रौद्योगिकी चालित दृष्टिकोण का विकास करने हेतु कई प्रायोगिक परियोजनाएं चला रहा है। वर्तमान में खरीफ 2020 और रबी 2021 में धान (चावल) और गेंहू की फसलों के लिए 100 जिलों में 7 चयनित राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय एजेंसिंयों के द्वारा प्रायोगिक परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं। ये एजेंसियां ग्राम पंचायत स्तर पर उपज का अनुमान लगाने के लिए मॉडलों का विकास करने हेतु ड्रोन के माध्यम से चित्र/डेटा लेने सहित मौसम, सुदूर संवेदी, मृदा नमी, जल संबंधी डेटा जैसे डेटा/तकनीकों के विभिन्न स्रोतों का उपयोग कर रही हैं। इस प्रयोजनार्थ डीजीसीए ने हाल ही में धान (चावल) और गेंहू की फसलों के लिए 100 प्रायोगिक जिलों में डेटा एकत्रित करने के लिए ड्रोन उड़ाने की सहमति दी है।

सांख्यिकी रूप से सक्षम और उपयुक्त मॉडल को अंतिम रूप देने/विकास करने से यह पीएमएफबीवाई के तहत शीघ्र उपज का अनुमान लगाने और समय पर दावों का निपटान करने के रूप में किसानों की मदद करेगा।

*****